बरेली मामला और दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली

कुछ हफ्ते पहले, उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली एक महिला को कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया, जो सुर्खियों में छाई रही। चुनिंदा मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा दोहराई गई कहानी ने एक ऐसी महिला की तस्वीर पेश की जिसने बलात्कार के आरोपों को बेशर्मी से गढ़ा था। बेशक, इसने इस हानिकारक रूढ़ि को कायम रखा कि महिलाओं द्वारा झूठे दावे करना आम बात है। लेकिन, मुकदमे की कार्यवाही में गहराई से जाने पर हमारे कानून प्रवर्तन तंत्र और सामाजिक जटिलताओं की एक श्रृंखला सामने आती है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है (एसटी 15/2020 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), बरेली के समक्ष)।

सुस्त जांचः

2019 में पूजा (बदला हुआ नाम) की माँ ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी लापता है और उसे शक है कि रमेश (बदला हुआ नाम) ने उसका अपहरण किया है। लेकिन पूजा कुछ दिनों बाद यह कहते हुए सामने आई कि उसे रमेश दिल्ली ले गया था और रमेश और कई अन्य लोगों ने उसकी माँ और बहन की जानकारी में उसके साथ बलात्कार किया था। उसने दावा किया कि वह दिल्ली से भागकर अपने घर आ गई थी। उसकी उम्र का कोई सबूत उपलब्ध नहीं था, लेकिन एक बाहरी मेडिकल जांच में उसकी उम्र 18 साल पाई गई, न कि 15 साल की, जैसा कि उसने दावा किया था। यौन उत्पीड़न के किसी भी सबूत के लिए अभियोजन पक्ष के मामले के लिए अधिक गहन जांच महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया। एक और तथ्य यह है कि वह एक विवाहित महिला है।

मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज किया गया और रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान अदालत में दिए गए अपने पहले बयान में उसने कहा कि उसका अपहरण किया गया था और उसके साथ बलात्कार किया गया था। चार महीने बाद जिरह में उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे रमेश के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया था क्योंकि माँ और रमेश के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी थी।

उसने यह भी कहा कि एक पुलिस अधिकारी ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। अभियोजन पक्ष के मामले में स्पष्ट खामियों के आधार पर, जैसे कि उसके अपहरण और बरामदगी पर उसके बयानों में विरोधाभास, जांच अधिकारी की लापरवाही के कारण चिकित्सा साक्ष्य की कमी और उसका मेडिकल परीक्षण कराने से इनकार करना, रमेश को 2024 में बरी कर दिया गया। पूजा के खिलाफ झूठी गवाही का मामला दर्ज किया गया, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया और कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बरेली के समक्ष एससी संख्या 215/2024)।

यह मामला पुलिस जांच के प्रति उदासीन दृष्टिकोण का एक स्पष्ट उदाहरण है और जहां अभियोजन पक्ष ने मामले को एक साथ जोड़ने का प्रयास भी नहीं किया। चार्जशीट दाखिल करने के समय, पूजा के बयान और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसके लापता होने के तथ्य का समर्थन करने के अलावा, रमेश के खिलाफ बिल्कुल भी सबूत नहीं था। बेशक, यौन उत्पीड़न में अभियोक्ता का बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एक ऐसा मामला था जहां उसे दूसरी जगह ले जाने का दावा किया गया था और जहां कई साथी कथित रूप से शामिल थे। लेकिन उन कोणों की जांच नहीं की गई। किसी भी बिंदु पर रमेश को पूजा के साथ रखने के लिए कोई परिस्थितिजन्य सबूत नहीं है। बलात्कार के दावे की पुष्टि करने के लिए कोई मेडिकल सबूत नहीं है। पूजा के

लापता होने पर माँ द्वारा रमेश को फोन करने का दावा किया गया है, लेकिन इसे साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं रखा गया है। कथित अपराध स्थल - दिल्ली में एक कमरा - अज्ञात और बिना जांच के रहा, और पूजा द्वारा पहने गए कपड़ों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भी एकत्र नहीं किया गया। यहां तक कि जिस किराए की संपत्ति में रमेश रह रहा था, उसकी भी जांच नहीं की गई। साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया साइट मैप पूजा के घर के सामने के दरवाजे को दिखाता है क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि उसे उनके घर से अगवा किया गया था। पूजा के मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के अनुसार, सब्जी मंडी, जहाँ से उसे ले जाया गया था, की जाँच नहीं की गई। हालाँकि यह आरोप लगाया गया था कि रमेश की माँ और बहन ने बलात्कार को देखा था, लेकिन उन पर न तो उकसाने का आरोप लगाया गया और न ही गवाह के तौर पर उनकी जाँच की गई।

कई हितधारकों ने इस मामले को अनदेखा कर दिया, जो इस मामले में एक बहुत ही कमजोर मामला रहा है। सीआरपीसी की धारा 173(8) मजिस्ट्रेट को दोषपूर्ण जांच के मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की अनुमति देती है। हालांकि, इस मामले में, मजिस्ट्रेट ने जांच में स्पष्ट खामियों के बावजूद मामले को सुनवाई के लिए सौंप दिया। मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा (172(2) के तहत केस डायरी मांग सकता था, जिससे जांच में विसंगतियां या अपर्याप्तताएं सामने आ सकती थीं। सरकारी अभियोजक द्वारा स्पष्ट रूप से कमजोर चार्जशीट का समर्थन करना एक ढीला रवैया और अदालत और जनता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफलता को दर्शाता है।

विचाराधीन हिरासत पर ध्यान केन्द्रित करें:

दुर्भाग्य से, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में मनमाने ढंग से और लंबे समय तक विचाराधीन हिरासत व्यापक है। इस मामले में, जहाँ एक व्यक्ति को चार साल से अधिक समय तक कारावास में रहना पड़ा, न्यायाधीश द्वारा यह नोट करने के अलावा कि जाँच में कुछ मुद्दे थे, जाँच अधिकारियों या अभियोजन पक्ष के प्रति जवाबदेही का चौंकाने वाला अभाव था। गलत तरीके से हिरासत में लिए गए लोगों के लिए कोई परिणाम नहीं होना दंड से मुक्ति की संस्कृति को बनाए रखता है और न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता में जनता के विश्वास को कम करता है।

मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान, अदालत में दिए गए उसके प्रारंभिक बयान तथा जिरह में पूजा द्वारा बताई गई घटनाएं, सभी अलग-अलग थीं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस पर जबरदस्ती की गई थी।

जिरह के दौरान, उसने अपनी मां और एक पुलिस अधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद, उसके झूठे बयान के मामले की सजा की सुनवाई के दौरान, पूजा के पति ने दावा किया कि उसने उसे यह दावा करने के लिए कहा था कि उसकी मां ने उसे अपहरण और बलात्कार के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था ताकि उन्हें इस मामले से और परेशान न होना पड़े। भले ही वह नाबालिग न हो, लेकिन वह स्पष्ट रूप से एक बहुत छोटी लड़की थी जिसे कई वयस्कों ने मजबूर किया था। उसे सजा सुनाने वाली अदालत ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा।

इसका मतलब यह नहीं है कि रमेश सिस्टम का शिकार था। कोविड-19 महामारी की भयावह पृष्ठभूमि के बीच बरेली की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलता रहा। यौन अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों के पीड़ितों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी।

वैसे तो आदर्श रूप से इन मामलों को चार्जशीट दाखिल करने के एक साल के भीतर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस समय-सीमा का पालन शायद ही कभी किया जाता है। इस मामले में मुकदमा 1,559 दिनों तक चला, जिसमें 109 सुनवाई हुई (ई-कोर्ट पोर्टल से डेटा)। डेटा यह भी दर्शाता है कि इनमें से ज़्यादातर सुनवाई सिर्फ स्थगन के कारण हुई, जिनमें से 13 कोविड-19 महामारी के कारण थीं। गवाहों की जांच नवंबर 2020 से फरवरी 2024 तक चली। ये समय-सीमा चौंकाने वाली है क्योंकि मामला अपने आप में जटिल नहीं था, क्योंकि इसमें केवल छह गवाह और छह साक्ष्य थे। इस पूरे समय में रमेश जेल में रहा।

फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थिति:

फास्ट-ट्रैक अदालतों का कामकाज आदर्श से बहुत दूर रहा है। आवश्यक बुनियादी ढांचे और समर्पित न्यायाधीशों के साथ नई अदालतें फास्ट-ट्रैक उद्देश्यों के लिए स्थापित नहीं की जाती हैं। इसके बजाय, मौजूदा अदालतों को आम तौर पर फास्ट-ट्रैक अदालतों के रूप में नामित किया जाता है, जिससे न्यायाधीशों को इन त्वरित मामलों के अलावा अपने नियमित केसलोड का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। इन प्रणालीगत चुनौतियों पर गौर किए बिना, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को हाल ही में 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है।

यह मामला भारत में जमानत के मुद्दे पर भी सवाल उठाता है। रमेश ने 2021 में सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की, लेकिन अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण इसे खारिज कर दिया गया। उसके परिवार के पास अपील दायर करने के लिए आर्थिक साधन नहीं थे, इसलिए वह बरी होने तक जेल में रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान जेलों में भीड़ कम करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, रमेश को इस अवधि के दौरान भी जमानत नहीं दी गई। और, नीतिगत

क्षेत्रों और संवैधानिक न्यायालयों में विचाराधीन हिरासत में कमी के पक्ष में लगातार चर्चा के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के भीतर की गंभीर वास्तविकता यह दर्शाती है कि कैसे उदासीनता और गरीबी इस तरह की हिरासत को लंबा खींचती है।

अंततः, इस मामले से जुड़ी बदनामी, जिसका हवाला महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की रूढ़ि को मजबूत करने के लिए दिया गया है, आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण आह्वान को रेखांकित करता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों को कमजोर करने के बजाय, यह मामला गलत और लंबी अवधि के कारावास के जोखिम को कम करने के लिए पुलिस जांच प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण में वृद्धि की आवश्यकता को उजागर करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वर्ष 2018 में लागू दंड विधि (संशोधन) अधिनियम के आधार पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई।
2. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को हाल ही में 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Que. Consider the following statements:

1. Fast Track Special Court was established on the basis of the Criminal Law (Amendment) Act implemented in the year 2018.
2. The Centrally Sponsored Scheme for Fast Track Special Courts has recently been extended till 2026.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: ''भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में लंबी अवधि के विचाराधीन कारावास के जोखिम को कम करने के लिए पुलिस जांच प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण में वृद्धि की आवश्यकता है।'' टिप्पणी करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में लंबी अवधि के विचाराधीन कारावास की स्थिति को संक्षिप्त में समझाएं।
- दूसरे भाग में इस समस्या को दूर करने के समाधानों में पुलिस जांच प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता की चर्चा करें।
- अंत में अपने सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।